गणेश जी की वैश्विक यात्रा — एक देश से दुनिया तक

दृष्टि शर्मा

भोपाल ,12 सितम्बर गणेश उत्सव देशभर में बड़े-बड़े पंडालों, जुलूसों और सार्वजनिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था.

19वीं शताब्दी के अंत तक गणेश उत्सव मुख्य रूप से घरों में निजी तौर पर मनाया जाता रहापुणे में पेशवा काल के दौरान गणेश उत्सव को राजकीय संरक्षण मिला था1818 में पेशवाओं के पतन के बाद यह उत्सव धीरे-धीरे निजी पारिवारिक आयोजन तक सीमित हो गया.

थाईलैंड : साल भर के आराध्य देव

यहां गणेश को 'फ्रा फिकानेट' कहा जाता हैथाई समाज में वे सिर्फ एक त्योहारी देवता नहीं, बल्कि कला, व्यापार और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं. खास बात यह है कि उनकी आराधना गणेश चतुर्थी तक सीमित नहीं अपितु पूरे साल होती है.

जापान : कांगितेन के रूप में

जापान में गणेश 'कांगितेन' या 'शोटेन' नाम से पूजे जाते हैंयह परंपरा भारत से सीधे नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के रास्ते जापान पहुंची और वहां अपनी अलग धार्मिक पहचान बना लीव्यापारी और कलाकार वर्ग में उनकी विशेष मान्यता है.

इंडोनेशिया : ज्वालामुखी के किनारे

पूर्वी जावा के माउंट ब्रोमो पर लगभग 700 साल पुरानी गणेश प्रतिमा स्थित है — वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक किनारेयहां का तेंगेर समुदाय गणेश को फल और अगरबत्ती अर्पित कर सुरक्षा की कामना करता है.

मॉरीशस : राष्ट्रीय अवकाश

मॉरीशस में गणेश चतुर्थी सार्वजनिक छुट्टी हैभक्त घर पर मिट्टी की प्रतिमा लाकर 10 दिन तक रोज पूजा करते हैं, फिर जुलूस के साथ नाचते-गाते है और पूरी श्रद्धा के साथ समुद्र या नदी तक जाकर विधिवत् विसर्जन करते हैं.

सार्वजनिक गणेशोत्सव के विस्तार में बाल गंगाधर तिलक की अहम भूमिका रही. ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंधों के बीच धार्मिक उत्सव लोगों के सामूहिक रूप से जुटने का एक माध्यम बन गया. 1894 में तिलक ने अपना सार्वजनिक गणपति स्थापित किया और इसके बाद पुणे समेत कई इलाकों में सार्वजनिक गणेश मंडलों का विस्तार हुआ.इस तरह 1890 के दशक में गणेश उत्सव घरों से निकलकर सार्वजनिक मंच तक पहुंचा और आगे चलकर महाराष्ट्र की एक बड़ी सांस्कृतिक परंपरा बन गया और आज विदेशो में भी मनाया जाता है.

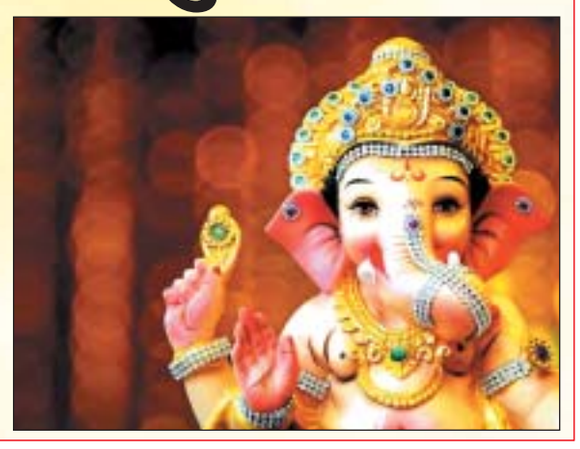

पार्टियों ने छिपाए प्रत्याशियों के अपराध

एडीआर रिपोर्ट में खुलासा : 5 राज्यों में 191 उम्मीदवारों के फार्म-सी 7 में नहीं दी जानकारी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 12 सितंबर. देश में हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के कारण बताने में राजनीतिक दलों ने नियम का उल्लघंन किया.

एडीआर ने 51 राजनीतिक दलों के 3,539 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया. जिनमें 1,405 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले बताए थे. इनमें से 191 उम्मीदवारों के लिए जरूरी कारण सार्वजनिक नहीं किए गए. राजनीतिक दलों ने 1,214 उम्मीदवारों के लिए फॉर्मेट सी-7 में जरूरी जानकारी जारी की थी. वहीं 191 यानी 14 प्रतिशत

उम्मीदवारों के लिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी. असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव में कुल 8,848 उम्मीदवार मैदान में थे. तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके लिए सी-7 में खुलासा उपलब्ध नहीं था. पश्चिम बंगाल में 55, केरल में 27, पुडुचेरी में 12 और असम में 10 उम्मीदवारों के की जानकारी उपलब्ध नहीं थी. सी-7 खुलासे का मकसद मतदाताओं को यह बताना है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद पार्टी ने उसे टिकट क्यों दिया. साथ ही यह भी बताना होता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि आयोग ने राजनीतिक दलों को वेबसाइट, सोशल मीडिया खातों और समाचार पत्रों में यह जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया. तमिलनाडु में एडीआर ने 1,162 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया. इनमें 473 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए थे. इनमें 72 उम्मीदवारों के लिए जरूरी खुलासा उपलब्ध नहीं था. पश्चिम बंगाल में 1,516 उम्मीदवारों में से 559 ने आपराधिक मामले घोषित किए थे.

एक जैसे कारण देने का भी दावा

एडीआर ने पाया कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए कारण कई मामलों में एक जैसे या दोहराए गए थे. खुलासों में आमतौर पर उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि, सामाजिक कार्य, अनुभव, लोकप्रियता, योग्यता और सीट के लिए उपयुक्तता जैसे कारण बताए गए. तमिलनाडु में एडीआर ने पाया कि भाजपा, अन्नाद्रमुक, द्रमुक और तमिलगा वेत्री कझगम समेत कुछ दलों ने आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के लिए अपने खुलासों में शब्दश- एक जैसे कारण दिए.

31 प्रतिशत उम्मीदवार ही टिकट के लिए सार्वजनिक

क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के भीतर उन्हें टिकट देने के कारण सार्वजनिक किए जाएं. ये कारण उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और मेरिट पर आधारित होने चाहिए, केवल उसकी जितने की क्षमता यानी विनेबिलिटी पर नहीं. पुडुचेरी में विश्लेषण किए गए 112 उम्मीदवारों में से 39 यानी 35 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे. इनमें 12 यानी 31 प्रतिशत उम्मीदवारों के लिए टिकट देने के कारण सार्वजनिक किए गए थे.

महिला स्वसहायता समूहों को 5 साल में मिलेगा 10 लाख करोड़ का लोन

'एक दीया आशीर्वाद का' से रोशन होगा देश

नई दिल्ली, 12 सितंबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को देशभर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, लखपति दीदियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया.

इस दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अगले पांच वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसमें व्यक्तिगत स्तर पर उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान शामिल होगा. वर्चुअल कार्यक्रम में देशभर से 6 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह की बहनें, लखपति दीदियां, ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी और लाभार्थी जुड़े. विभिन्न राज्यों की महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं ने किस तरह उनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव किया है.

17 सितंबर को जलेगा 'एक दीया आशीर्वाद का'

कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशवासियों से 17 सितंबर को शाम 7 बजे 'एक दीया आशीर्वाद का' जलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह दीपक प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की प्रगति और विकास के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होगा. चौहान ने बताया कि वे स्वयं 17 सितंबर को तेलंगाना के एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, आवास लाभार्थियों और किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की नारी शक्ति आत्मनिर्भरता और विकास की नई कहानी लिख रही है.

अंबानी-अडाणी की संपत्ति 1.41 लाख करोड़ घटी

- **फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की टॉप-100 अमीरों की सूची**

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 12 सितंबर. फॉर्च्यून इंडिया ने देश के टॉप-100 अरबपतियों की नई सूची जारी की है.

सूची के मुताबिक, देश के दो सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी की कुल संपत्ति में पिछले एक साल में 1.41 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है. इसके बावजूद दोनों अपनी-अपनी रैंकिंग पर कायम हैं. मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडाणी दूसरे स्थान पर हैं. टॉप-100 में

शामिल 30 उद्योगपतियों की संपत्ति में कुल 4.26 लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई. इनमें मुकेश अंबानी की संपत्ति सबसे ज्यादा करीब 82 हजार करोड़ रुपये घटी, जबकि गौतम अडाणी की संपत्ति में लगभग 59 हजार करोड़ रुपये की कमी आई. वहीं, दूसरी ओर 56 उद्योगपतियों की कुल संपत्ति में 7.70 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. सूची में शामिल 31 कारोबारियों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई.

आज का इतिहास

1759: ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध क्यूबेक का युद्ध लड़ा गया.

1899: अमेरिका में पहली बार वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत दर्ज की गई

1922: लीबिया के अल अजीजिया में तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस (136.4 सेल्सियस) दर्ज किया गया.

1948: सरदार वल्लभभाई पटेल के आदेश पर भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई शुरू की.

हमजा के वीडियो से हड़कंप

- **अमेरिका का ओसामा के बेटे हमजा के जिंदा होने का दावा**
- **अल-कायदा ने जारी किया वीडियो**

नई दिल्ली, 12 सितंबर. अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. 9/11 हमलों की 25वीं बरसी के मौके पर अल-कायदा के मीडिया विंग अस-सहाब ने करीब 50 मिनट लंबा वीडियो जारी किया है.

उक्त वीडियो में हमजा की पहले सार्वजनिक नहीं हुई फुटेज दिखाई गई है. हालांकि, इस वीडियो से यह स्वतंत्र रूप से साबित नहीं होता कि हमजा वर्तमान में जीवित है. हमजा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन का नामित उत्तराधिकारी माना जाता था. वर्ष 2019 में अमेरिकी आतंकवाद रोधी अभियान में उसके मारे जाने की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद से उसकी स्थिति को लेकर स्पष्ट और सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई थी. ऐसे में नए वीडियो ने खुफिया मामलों के जानकारों का ध्यान खींचा है. वीडियो का शीर्षक 11 सितंबर के हमलों के पच्चीस साल बताया गया है. इसमें हमजा को पारंपरिक सफेद पगड़ी पहने एक मिट्टी की दीवार के सामने बैठे दिखाया गया है.

एआई से बना डाले पीएमओ के फर्जी कार्ड

मुंबई में पकड़े गए 'नकली अफसर' का खुलासा

नवभारत न्यूज

मुंबई, 12 सितंबर. मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड प्लाजा में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर पहुंचने वाले 24 वर्षीय रोहन पारिख के मामले में पुलिस ने अदालत के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने चैट जीपीटी जैसे एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टूल्स की मदद से फर्जी पीएमओ पहचान पत्र और आधिकारिक पत्रों के ड्राफ्ट तैयार किए थे. बांद्रा की एस्प्लेनेड अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपी के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में पीएमओ से संबंधित पत्र तैयार करने के सबूत मिले हैं. पुलिस का दावा है कि रोहन वर्ष 2025 से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था. जांच एजेंसी ने आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने पुलिस की दलीलों को आगे की कस्टडी के लिए पर्याप्त नहीं माना और रोहन पारिख तथा उसके साथ मौजूद 49 वर्षीय दिलीप कुंडे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

पूर्व सैनिक बना था बॉडीगार्ड

मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी दिलीप कुंडे पूर्व सैन्यकर्मी है. पुलिस ने उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की है. पुलिस के अनुसार, कुंडे ने स्वीकार किया कि वह रोहन के व्यावसायिक बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा था. जांच में उसके हथियार लाइसेंस के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में शामिल होने से एक दिन पहले रोहन फर्जी पीएमओ आईडी और हथियारबंद गार्ड के साथ जियो वर्ल्ड प्लाजा पहुंचा था. सुरक्षा कर्मचारियों से विवाद के बाद मॉल प्रशासन की शिकायत पर बीकेसी पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

मंत्रालय के गलियारे से

क्या छिपाना चाह रहे अफसर

कन्हैया लोधी

राजधानी का मास्टर प्लान इन दिनों बर्निंग सब्जेक्ट बना हुआ है. इस सब्जेक्ट को लेकर पिछले दिनों आला अफसरों का दिल्ली दौरा भी बेहद चर्चा में बना रहा. सबने माना कि सरकार के ये अफसर दिल्ली में सरोकार वाले लोगों के साथ प्लान को लेकर जबर्दस्त माथापच्ची कर रहे थे, लेकिन बाद में एक अफसर ने इस मामले को ठंडा करने के लिए एक नया शिगूफा चल दिया. उन्होंने दलील दी कि वे तो अपने पापाजी से मिलने के लिए दिल्ली गई थी. अब बस फिर क्या था, जिसको जो अनुमान लगाना है, लगाते रहे. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बड़े सब्जेक्ट को लेकर क्या बड़े स्तर पर कुछ छिपाने की भी कोशिश की जा रही है, यह तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा.

जून की घटना और सितंबर में वायरल

प्रदेश के एक माननीय विधायक से जुड़ा घटनाक्रम हाल ही में तेजी से वायरल हुआ. माननीय के साथ मारपीट जैसी बड़ी घटना हो गई, घटना भी ऐसी कि बस जबड़ा टूटने से बच गया. लेकिन माननीय ने किसी फोरम में कोई शिकायत तक नहीं की. सत्ताधारी दल के विधायक के साथ हुई इस घटना के बारे जो जानकारी छन कर आ रही है वह ये कि ये घटना सितंबर की नहीं बल्कि जून की है, ये और बात है कि वायरल अब जाकर हुई. अब माननीय के शिकायत नहीं करने की वजह भी कुछ-कुछ सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि यदि मामला कुछ ज्यादा ही सार्वजनिक हो जाता तो फिर उनके चरित्र पर भी सवाल उठ सकते थे, इसलिए उन्होंने मामले में मौन धारण करना ही बेहतर समझा.

आखिरकार ताकतवर कॉडर ने दिखा दिया रूतबा

प्रदेश में तीन सबसे ताकतवर कॉडर हैं, जो कि सरकार चलाने में सबसे प्रभारी भूमिका निभाते हैं. इस तीनों की कॉडर के बीच कई बार वर्चस्व को लेकर जंग की स्थिति बनती है, लेकिन सरकार चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला कॉडर बाकी दो कॉडर पर हावी ही रहता है. हाल ही में एक ऐसे ही कॉडर के जिले में पदस्थ रहने वाले अफसर को सबसे ताकतवर कॉडर के समकक्ष अफसर के अधीन कर दिया गया. इस व्यवस्था का लंबे समय से विरोध चल रहा था, लेकिन आखिरकार मैदान में हावी रहने वाला कॉडर ने अपना रूतबा दिखा दिया. अब प्रभावित कॉडर इसे जंगलराज की संज्ञा देने में लगा है.

कद बढ़ाने की तैयारी में नेता

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ गई है. पैसा जमा कराने का एक बेरियर पार कर लिया है. कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि वे कार्यक्रम बेहद सफल होगा, इसकी तैयारी भी की जा रही है. कुछ कुछ नेता इसे अपने कद में इजाफा करने के मौके के रूप में भी देख रहे हैं. अभी दिल्ली दरबार में जीतू पटवारी की एकतरफा गुंज है, ऐसे में इस इवेंट के बहाने दूसरे नेता भी राहुल गांधी की आंखों का तारा बनने की जुगत में लग गए हैं. अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं.

सुरंग की विशेषता

- 28 सुरंग है प्रोजेक्ट में
- 22 सुरंगों का काम पूरा
- 125 किलो मीटर है प्रोजक्ट की लंबाई
- 12 नए स्टेशन
- 100 किलोमीटर प्रति घंटा यात्री ट्रेनों की अधिकतम गति
- 65 किमी प्रति घंटा मालगाड़ियों की अधिकतम गति
- 19 पुलों की संख्या
- 213 किमी मुख्य निकास सुरंगों की कुल लंबाई

ऋषिकेश रेल टनल ब्रेकथ्रू...लहराया तिरंगा

ऋषिकेश. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली टनल की निकास शनिवार को सुरंग आर-पार (ब्रेकथ्रू) हो गई. सुरंग आर-पार होने पर निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा लेकर खुशी मनाई. अब मुख्य सुरंग को आर-पार करने की तैयारी और तेज की जा रही है.

आईआईआईटी इलाहाबाद ने प्लेसमेंट में रचा नया इतिहास

4 छात्रों ने हासिल किया 1.58 करोड़ का पैकेज

नवभारत न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज, 12 सितंबर. आईआईआईटी इलाहाबाद के बीटेक 2026 बैच ने प्लेसमेंट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. संस्थान के इतिहास में पहली बार चार छात्रों को 1.58 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है.

प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर 480 बीटेक छात्रों में से 462 का चयन हुआ. इस तरह कुल प्लेसमेंट दर 96.25 प्रतिशत रही. चयनित बीटेक छात्रों का औसत सालाना पैकेज करीब 32.50 लाख रुपये रहा, जबकि 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष दर्ज किया गया.

नाम सुधार सूचना

मैं अमजद मंसूरी (Amjad Mansuri) तनय मोहम्मद नमान मंसूरी हाउस नं.125 वार्ड नं.12 गोपाल टोला नागौद जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना हुआ है जिसका नं.MP1920030002257 है जिसमें मेरा व पिता का नाम Amjad Mansoori S/o Shri MD.R Mansoori दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम अमजद मंसूरी (Amjad Mansuri) तनय मोहम्मद नमान मंसूरी (Mohammad Naman Sansuri) जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है अत: मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में दर्ज नाम Amjad Mansoori S/o Shri MD.R Mansoori के स्थान पर सही नाम अमजद मंसूरी (Amjad Mansuri) तनय मोहम्मद नमान मंसूरी (Mohammad Naman Sansuri) दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

गुंडा एक्ट पुलिस का हथियार नहीं

जबरन कार्रवाई पर यूपी हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

नवभारत न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज, 12 सितंबर. उत्तर प्रदेश में यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है.

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गोंडा निवासी जाहिद अली के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के शक्तिशाली कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को परेशान करने या उत्पीड़न के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता. गोंडा जिला प्रशासन ने 11 मई 2026 को जाहिद अली को गुंडा घोषित करते हुए छह महीने के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया

था. प्रशासन ने कार्रवाई के लिए वर्ष 2010 और 2020 के आपराधिक मुकदमों के साथ पुलिस की बीट सूचना रिपोर्ट को आधार बनाया था. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने सामने आया कि 2010 के जिस मुकदमे को कार्रवाई का आधार बनाया गया, उसमें जाहिद अली को 2017 में ही बरी किया जा चुका था. कोर्ट ने कहा कि बरी हो चुके मामले को किसी व्यक्ति को आदतन अपराधी साबित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता. अदालत ने पुलिस रिपोर्ट में पुराने मामले को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने 2020 के मुकदमे को भी गुंडा एक्ट लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना. अदालत ने कहा कि सिर्फ एक लंबित मुकदमा किसी व्यक्ति के आदतन अपराधी होने का प्रमाण नहीं है. साथ ही 2020 के मुकदमे और 2026 में की गई कार्रवाई के बीच करीब छह साल का अंतर था. ऐसे में कार्रवाई के लिए उचित संबंध भी दिखाई नहीं देता. पुलिस की बीट रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना, (म.प्र.)

संभाग सतना एवं सदस्य सचिव, जिला वॉश तकनीकी समिति सतना

क्रमांक / 948 /निविदा/ग्रायासेवा/2026-27 सतना, दिनांक 11.09.2026

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 04/2026-27

जिला वॉश तकनीकी समिति, सतना द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन - संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 की कंडिका 12 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण नल जल योजनाओं के वृहद मरम्मत, रख-रखाव एवं स्त्रोत तथा पाइप लाइन विस्तार कार्यों हेतु कंडिका 14 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एजेंसियों को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध (empanel) करने के लिए पात्र आवेदकों से निर्धारित समयसीमा अनुसार ऑनलाईन http://mptenders.gov.in पोर्टल पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेण्डर नंबर	जिले का नाम	जिले में जनपद पंचायतों के नाम	सूचीबद्धता शुल्क (रु.)	निविदा दस्तावेज शुल्क (रु.)	सूचीबद्धता की अवधि (माह)
1	3	4	5	6	7	8
1	2026_RES_535681	सतना	सोहावल, नागौद, उचेहरा, रामपुर बघेलान एवं मझगवां	50000.00	1000.00	24 माह
2	2026_RES_53568	मैहर	मैहर, अमरपाटन एवं रामनगर	50000.00	1000.00	24 माह

कंडिका (1) निविदा संबंधी समय सारणी

क्र.	विवरण	प्रारंभ का दिनांक समय	अंतिम दिनांक/समय
1	निविदा क्रय करने की तिथि	17.09.2026, 10.00 AM	27.09.2026, 5.30 PM
2	निविदा संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन जमा की तिथि	18.09.2026, 11.00 AM	27.09.2026, 5.30 PM
3	निविदा संबंधी तकनीकी दस्तावेज का परीक्षण की तिथि	06.10.2026, 10.00 AM	-
4	प्री-बिड मीटिंग स्थल जिला पंचायत सभागार सतना	22.09.2026, 1.30 PM	

तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 06.10.2026 प्रात: 10.00 से इस कार्यालय में खोले जावेगे। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने हेतु विस्तृत निविदा व अन्य विवरण http://mptenders.gov.in वेबसाईट पर एवं कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है । कि वे अंतिम दिवस की प्रतिक्षा न कर निर्धारित समयसारणी अनुसार निविदा की आन-लाईन प्रकिया पूर्ण करें. वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नाहीं होगा। ई - निविदा जारी होने के बाद अगर निविदा में कोई संशोधन किया जाता है, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी, संशोधन केवल शासकीय पोर्टल http://mptenders.gov.in पर आन-लाईन ही जारी किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना
सदस्य सचिव, जिला वॉश तकनीकी समिति
जिला - सतना म.प्र.

G-18492 / 26